नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org, ructarashtriya@gmail.com

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305001 (राज.)

अध्यक्ष : डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर मो. 9414452369, 9983007575

महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2017-18/03 पौष शु. १ वि. स. २०७४ तदनुसार 19 दिसम्बर, 2017

(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार।

56वें प्रांतीय अधिवेशन के आयोजन की सूचना, पदनाम परिवर्तन के संबंध में हुई प्रगति, उच्च शिक्षा मंत्री जी, मानव संसाधन विकास मंत्री जी व आयुक्त से भेंट की जानकारी एवं संगठन की अन्य गतिविधियों के विवरण सहित यह परिपत्र प्रस्तुत है।

56 वाँ प्रांतीय अधिवेशन 8-9 जनवरी को बीकानेर में आयोज्य

संगठन का 56वाँ प्रदेश अधिवेशन माघ कृ. ७-८ विक्रम संवत् २०७४ तद्नुसार दिनांक 8 व 9 जनवरी 2018 को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विजय भवन पैलेस कॉम्पलैक्स, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल, बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। 8 जनवरी 2018 को प्रातः 11 बजे से अधिवेशन प्रारम्भ होगा। प्रथम दिन उद्घाटन समारोह, देराश्री स्मृति व्याख्यान एवं खुला सत्र आयोजित किए जाएँगे। 9 जनवरी 2018 को प्रातः 9 बजे शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसका विषय *''उच्च शिक्षा में परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली : दशा एवं दिशा''* है। शिक्षक साथियों से आग्रह है कि संगोष्ठी हेतु अपना शोध पत्र info@ructarashtriya.org पर भिजवाएँ। शैक्षिक संगोष्ठी के पश्चात् समारोप कार्यक्रम सम्पन्न होगा। अधिवेशन के विभिन्न सत्रों में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, राजनैतिक व्यक्तित्वों, शिक्षाविदों तथा अखिल भारतीय अधिकारियों का सान्निध्य प्राप्त होगा। सभी शिक्षक साथियों से विनम्र अनुरोध है कि अधिवेशन में पूरे समय रुक कर सक्रिय सहभागिता करें। अधिवेशन में पंजीयन शुल्क 200 रु. प्रति संभागी है। सभी इकाई सचिवों से आग्रह है कि स्थानीय इकाई की बैठक अविलम्ब आयोजित कर समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव पारित करवा कर ई-मेल से भिजवाएँ।

शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1. **पदनाम परिवर्तन के नियम कार्मिक विभाग एवं लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत** - मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी द्वारा 11 जनवरी 2017 को रुक्टा (राष्ट्रीय) के अधिवेशन में हजारों शिक्षकों के समक्ष महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर करने की घोषणा के पश्चात् भी नौकरशाही द्वारा उत्पन्न विभिन्न अड़चनों के विरुद्ध संगठन के लगातार संघर्ष की परिणति स्वरूप गत 15 अक्टूबर 2017 को पदनाम परिवर्तन की अधिसूचना के संशोधित प्रारूप को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी थी। संगठन द्वारा निरन्तर इस फाईल का ट्रेक करते हुए पदनाम परिवर्तन के नियम शीघ्र पारित करने हेतु संबंधित पक्षों पर दबाव बनाया गया। फलस्वरूप कार्मिक विभाग ने गत 28 नवम्बर को उक्त अधिसूचना के प्रारूप को स्वीकृत कर दिया है। लोक सेवा आयोग ने भी संगठन की सक्रियता के चलते अपेक्षित तीव्रता दिखाते हुए कतिपय संशोधनों के साथ पदनाम परिवर्तन नियमों के प्रारूप को स्वीकृत कर दिया है। संगठन को आशा है कि प्रदेश अधिवेशन से पूर्व विधि विभाग की क्लियरेंस व केबिनेट अनुमोदन पश्चात् पदनाम परिवर्तन के विस्तृत नियम जारी हो सकेंगे।
2. **उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भेंट** - संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 7 दिसम्बर 2017 को उच्च शिक्षा मंत्रीजी श्रीमती किरण माहेश्वरी जी से भेंट कर शिक्षकों की लम्बित समस्याओं को शीघ्र निपटाने की माँग की। मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि पदनाम परिवर्तन का नोटिफिकेशन इसी माह जारी करवाने के प्रयास हैं, इस हेतु लोक सेवा आयोग एवं विधि विभाग से संबंधित अंतिम औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरी करने हेतु संगठन की भावना के अनुरूप अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्राचार्य/उपाचार्य की डीपीसी, 2015 तक बकाया वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के लम्बित प्रकरणों, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक आदि के अतिशीघ्र समाधान की बात कही। मंत्रीजी ने बताया कि जून 2013 के बाद लम्बित पे बैंड-4 की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी खामियों के अविलम्ब निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में मंत्रीजी से लोक सेवा आयोग से महाविद्यालय शिक्षक चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब, नवीन कार्यभार के अनुसार पद सर्जन, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन भर्ती पश्चात् हुए रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने, शिक्षक दिवस पर उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के सम्मान सहित अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। विश्वास है कि संगठन के निरन्तर दबाव एवं सक्रियता के चलते लम्बित समस्याओं का समाधान हम क्रमशः प्राप्त कर सकेंगे।
3. **मानव संसाधन विकास मंत्री जी से भेंट** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने 15 नवम्बर 2017 को शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जी जावड़ेकर से विस्तृत भेंटवार्ता की। संगठन की ओर से नवीन यू.जी.सी. वेतनमान घोषित करने पर मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इसमें रही विसंगतियों को दूर करने की माँग की। संगठन द्वारा शिक्षकों का पक्ष विस्तार से रखते हुए बताया गया कि अभी तक यू.जी.सी.

वेतनमानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का 80 प्रतिशत तक अंश 5 वर्ष तक केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता था। इस वेतनमान में यह अंश 50 प्रतिशत तक घटाते हुए समय अवधि भी केवल 39 माह कर दी है। संगठन ने मंत्री जी से सम्पूर्ण देश में एक समान वेतनमान लागू करने के लिए पूर्ववर्त्ती वेतनमानों के समान ही वित्तीय सहायता देने की माँग की।

नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में पीएच.डी. एवं एम.फिल. की अग्रिम वेतनवृद्धियों के प्रावधान को समाप्त करने का संगठन ने विरोध करते हुए उच्च शिक्षा में शोध का बढ़ावा देने हेतु उन्हें जारी करने हेतु अपेक्षित संशोधन की माँग की। संगठन ने मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि अभी तक यू.जी. एवं पी.जी. प्राचार्य को प्रोफेसर के समकक्ष वेतनमान दिया जाता रहा है किन्तु इस वेतनमान में यू.जी. प्राचार्य को एसोसिएट प्रोफेसर की ग्रेड देने का प्रावधान रखा है जो कि न्यायसंगत नहीं है। संगठन ने मंत्रीजी से माँग की कि पूर्व वेतनमानों के अनुरूप ही यू.जी. प्राचार्य को भी प्रोफेसर के समकक्ष वेतनमान दिया जाये। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने विस्तृत माँग पत्र प्रस्तुत करते हुए नवीन यू.जी.सी. वेतनमान सम्पूर्ण देश में एक समान रूप से 1 जनवरी 2016 से लागू करने हेतु केन्द्र से बाध्यकारी निर्देश जारी करने, ऑरियेन्टेशन तथा रिफ्रेशर कोर्स की छूट की अवधि 31 दिसम्बर 2017 तक बढ़ाने, कार्यरत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से मुक्त रखने, 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना बहाल करने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु सम्पूर्ण देश में एक समान 65 वर्ष करने, शिक्षा सेवा संवर्ग पृथक से बनाये जाने, शिक्षकों को सी.ए.एस. लाभ हेतु ए.पी.आई. योजना पर पुनः विचार कर तर्कसंगत बनाने, पूर्व सेवा का लाभ सभी शिक्षकों को देने, शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन व नियंत्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतंत्र व स्वायत्त शिक्षा नियामक आयोग बनाने तथा सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 10 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने सहित अन्य विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही करने की माँग की। श्री जावडेकर जी सभी विषयों को गंभीरता से समझा तथा अधिकारियों के साथ चर्चा पर अपेक्षित कार्यवाही का मंतव्य व्यक्त किया।

4. **उच्च शिक्षा मंत्री जी का अभिनंदन** – शिक्षकों की वर्षों से लम्बित पदनाम परिवर्तन की माँग को मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाने एवं तत्पश्चात नौकरशाही द्वारा उत्पन्न विभिन्न अड़चनों के समाधान में लगातार सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग के लिए उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी का बीकानेर, अजमेर, कोटा, जोधपुर एवं अलवर संगठन इकाईयों द्वारा चुनरी ओढ़ाकर, सम्मान पत्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया।

5. **जून 2017 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ** – संगठन निरन्तर भेंटवार्ताओं एवं पत्रों के माध्यम से कॅरियर एडवांसमेन्ट योजना का लाभ देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समयबद्ध आयोजित करने की माँग करता आया है। संगठन के प्रयासों के क्रम में 5 दिसम्बर 2017 को सी.ए.एस. के अन्तर्गत 30 जून 2017 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के पात्र शिक्षकों को यह लाभ देने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। संगठन के ध्यान में

आया है कि कई शिक्षक साथियों का वरिष्ठ/चयनित वेतनमान जून 2017 से दिसम्बर 2017 के मध्य ड्यू हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें भी आवेदन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए संगठन ने सरकार से माँग की है कि 30 जून 2017 के स्थान पर 31 दिसम्बर 2017 तक पात्र शिक्षकों के आवेदन माँगे जाएँ। संगठन इस हेतु भी प्रयासरत है कि वरिष्ठ/चयनित वेतनमान के साथ ही 30 जून 2013 के बाद ड्यू पे बैंड-4 का लाभ देने की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ की जाए।

6. **30 जून 2015 तक लम्बित वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु लोक सेवा आयोग को पत्र प्रेषित** - गत जुलाई 2016 में 30 जून 2015 तक पात्र शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया था, किन्तु 172 प्रकरणों के आवेदन पत्रों में कतिपय कमियों के कारण उन्हें उक्त लाभ नहीं मिल सका था। संगठन के लगातार प्रयासों की परिणति में 30 जून 2015 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के पात्र शिक्षकों को सी.ए.एस. के अन्तर्गत लाभ देने के लिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक हेतु सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग से स्क्रीनिंग समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारित होने पर पात्र शिक्षकों को अपेक्षित लाभ मिल सकेगा।

7. **आयुक्त महोदय से भेंट** - 3 नवम्बर एवं उसके पश्चात् 7 दिसम्बर 2017 को संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पेडणेकर व संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.) से भेंट कर शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं की समाधान प्रक्रिया में गति लाने की माँग की। वार्ता के विषयों में लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति देने, 30 जून 2013 के पश्चात् पे बैंड-4 देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के वेतन बिल बनाने हेतु प्राचार्यों को निर्देश देने, शारीरिक शिक्षकों का पदनाम परिवर्तन करने, प्राचार्य व उपप्राचार्य पद की डी.पी.सी. करने, वरिष्ठ/चयनित वेतनमान के लंबित प्रकरणों का समाधान व नवीन आवेदन मँगवाने सहित अन्य विषय शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि संगठन की माँग पर चार विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया 7 नवम्बर से प्रारम्भ की जा रही है। इसके बाद जैसे जैसे अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होता जाएगा उन्हें तुरन्त नियुक्ति पत्र जारी किये जायेंगे। संगठन को जानकारी दी गई कि शिक्षकों के वेतन बिल रोकने हेतु आयुक्तालय से कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं, प्राचार्यों द्वारा अपने स्तर पर संतुष्ट होकर वेतन बनाया जाना है। अधिकारियों ने वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु नवीन आवेदन मँगाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन भी संगठन को दिया।

8. **आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के वेतन रोकने एवं प्राचार्य स्तर पर स्वीकृत पे-बैंड-4 को गलत मानने का विरोध** - आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा 1 जनवरी 2006 के बाद प्राचार्य स्तर पर बिना विभागीय अनुमोदन के पे बैंड-4 का लाभ गलत मानने का संगठन ने पुरजोर विरोध किया है। संगठन ने विस्तृत तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ पे बैंड-4 के परिलाभ की वसूली रोकने की माँग की है। संगठन ने यह पक्ष भी रखा कि यदि किसी शिक्षक के दस्तावेज अथवा वेतन नियतन में

कोई कमी है तो सर्वप्रथम उसे पक्ष रखने का मौका दिया जाए और चूँकि इन सब प्रक्रियाओं में समय लगना है तो ऐसे में प्रक्रिया पूर्ण होने तक शिक्षकों का वेतन रोकना न्यायसंगत नहीं है। सेवा पुस्तिका जाँच के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोका जाए। संगठन को आशा है कि इस संदर्भ में शीघ्र ही सकारात्मक आदेश प्रसारित होंगे।

9. **महाविद्यालयों में रिक्त अशैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया में प्रगति** - संगठन लम्बे समय से महाविद्यालयों में रिक्त पड़े अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की माँग करता आया है। संगठन के लगातार प्रयासों के चलते 130 प्रयोगशाला सहायकों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है एवं इनके दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् शीघ्र ही पदस्थापन हो सकेगा। इसी प्रकार 217 लिपिकों हेतु भी चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इनका भी शीघ्र पदस्थापन करवाने के लिए संगठन प्रयासरत है।

10. **लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की पदस्थापन प्रक्रिया प्रारम्भ** - संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री जी से एवं अधिकारियों से भेंटवार्ताओं में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण महाविद्यालयों में आ रही समस्याओं के निवारण की नियमित अंतराल पर माँग की है। संगठन के प्रयासों से लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के परिणाम घोषित होने के साथ ही क्रमशः विभाग ने पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। संगठन लगातार प्रयासरत है कि लोक सेवा आयोग द्वारा शेष विषयों के भी साक्षात्कार शीघ्र आयोजित किये जाकर विभाग द्वारा तत्परता से पदस्थापन प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

11. **मार्च 2018 तक शिक्षकों के संभावित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त** - राज्य में उच्च शिक्षा के लगातार प्रसार के साथ उच्च शिक्षा कैडर में शिक्षकों के लगभग 6000 पद हो चुके हैं। वर्तमान में लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन 1248 पदों पर चयन में समय लगने से कैडर में शिक्षकों के अनेक पद और रिक्त हो गये हैं। भविष्य में महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या उत्पन्न न हो इसको दृष्टिगत रखते हुए संगठन ने आगामी वर्ष में रिक्त होने वाले शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया उन पदों के रिक्त होने से पूर्व ही प्रारम्भ करने की माँग की थी। संगठन की सक्रियता एवं प्रयासों के चलते मार्च 2018 तक शिक्षकों के रिक्त होने वाले संभावित 939 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से अग्रिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है। संगठन का प्रयास है कि इन पदों पर चयन प्रक्रिया समय पर प्रारम्भ हो जाये।

12. **उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों से अभद्र व्यवहार का विरोध** - उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा गत 15 नवम्बर एवं 25 नवम्बर को राजकीय महाविद्यालय हिण्डौन सिटी में दुर्भावना के साथ किए निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय शिक्षकों के साथ किए दुर्व्यवहार एवं उपस्थिति पंजिका में अनाधिकृत रूप से काट-छाँट करने की संगठन ने कड़ी निंदा की है। संगठन ने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखकर माँग की है कि वेतनमान एवं प्रोटोकॉल में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अपमानजनक व्यवहार को शिक्षक कदापि सहन नहीं करेंगे। संगठन ने उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पर समुचित कार्यवाही करने तथा आवश्यक होने पर प्राचार्य के समकक्ष अथवा वरिष्ठ अधिकारी को ही महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु लगाये जाने की माँग मुख्यमंत्री जी से की है।

सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

1. **प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न** - संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक डॉ. दिग्विजयसिंह की अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 2017 को देराश्री शिक्षक सदन जयपुर में सम्पन्न हुई। सामूहिक सरस्वती वंदना के पश्चात् महामंत्री ने गत बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। महामंत्री ने गत बैठक के बाद संगठन की गतिविधियों का लेखा-जोखा रखते हुए मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री व मानव संसाधन विकास मंत्री से भेंट के बारे में विस्तार से बताया तथा पदनाम परिवर्तन सहित विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप हुई प्रगति की जानकारी सदन को दी। तत्पश्चात् सदस्यों द्वारा अन्य लंबित शिक्षक समस्याओं को विस्तार से सदन के समक्ष रखा गया तथा उनके समाधान हेतु अपेक्षित कार्यवाही की माँग की गई। महामंत्री ने सदन को सभी समस्याओं पर मजबूती से संघर्ष करने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि संगठन अहर्निश शिक्षक एवं शिक्षा हित में शिक्षकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने हेतु संकल्पबद्ध है।

   बैठक के अगले सत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री श्री जे. पी. सिंघल जी ने केन्द्र द्वारा नवीन यू.जी.सी. वेतनमान जारी करने हेतु महासंघ के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि संगठन की इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर निरन्तर वार्ताएँ हुई हैं तथा शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा गया है। संगठन की निरन्तर जागरुकता एवं सक्रियता के चलते कई सकारात्मक सहमतियाँ बनी हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने पर इसका अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तय की जाएगी।

   इसके बाद वार्षिक अधिवेशन की तिथि व स्थान पर चर्चा की गई। सदन द्वारा अधिवेशन की तिथि 8-9 जनवरी 2018 तय की गई तथा स्थान तय करने हेतु अध्यक्ष एवं महामंत्री को अधिकृत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेन्द्र जी कपूर ने कहा कि प्रत्येक इकाई उपक्रमशील बने इस हेतु सामूहिक एवं व्यक्तिगत नवाचार आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्त्ताओं से प्रवास करने का आह्वान करते हुए प्रेमभाव से संगठन कार्य बढ़ाने पर जोर दिया। अधिवेशन को स्ववित्तपोषित करने तथा आयोजन के बढ़ते खर्च को देखते हुए सदस्यता के साथ अधिवेशन शुल्क लेने का प्रस्ताव साधारण सभा में रखने का सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। सदन ने एकमत से यह प्रस्ताव भी पारित किया कि संगठन की गतिविधियों हेतु एक स्थान लेने हेतु ट्रस्ट बनाकर प्रयास किया जाए इसमें संगठन की बचत से सहभाग दिया जाए।

   अध्यक्षीय उद्‌बोधन देते हुए डॉ. दिग्विजयसिंह ने कहा कि समाज हमारा अंकेक्षण करता है, उस पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में गत बैठक के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथी डॉ. वी. के. जैन भरतपुर, डॉ. राजवीर सिंह भरतपुर, डॉ. कमलेश दीक्षित कोटा, प्रो. अतरसिंह जोधपुर को

श्रद्धांजलि अर्पित की गई व दो मिनट का मौन रख कर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक समाप्त हुई।

2. **राष्ट्रीय कार्यकारिणी, साधारण सभा एवं महिला संवर्ग कार्यसमिति बैठक सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, साधारण सभा व महिला संवर्ग की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक 27 से 29 अक्टूबर 2017 तक अमरावती (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुई। 27 अक्टूबर को महिला कार्यसमिति की बैठक में महिला शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया गया तथा उनके समाधान के लिए सुझाव दिए गए। 28 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 17 राज्यों के राज्य संगठन व विश्वविद्यालय स्तरीय संगठनों द्वारा वृत्त निवेदन किए गए। बैंगलुरु में सम्पन्न शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान एवं दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय संगोष्ठी की समीक्षा की गई। संगठन मंत्री श्री महेन्द्र जी कपूर ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए 24 व 25 फरवरी 2018 को दिल्ली में आयोज्य अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ''वसुधैव कुटुम्बम्'' के बारे में विस्तार से चर्चा की।

29 अक्टूबर को सम्पन्न महासंघ की राष्ट्रीय साधारण सभा में गत बैठक की कार्यवाही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित अंकेक्षित आय-व्यय व महामंत्री प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साधारण सभा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत तीन प्रस्तावों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से स्वीकार किया। स्वीकृत प्रस्ताव हैं-(i) शिक्षा में निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन - वर्तमान मूल्यांकन पद्धति की कमियों को दूर करते हुए ऐसी मूल्यांकन पद्धति बने जिसमें शिक्षार्थी के बौद्धिक स्तर के साथ-साथ उसके व्यवहारिक ज्ञान, सहशैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी व नैतिक मूल्यों तथा अभिरुचियों का मूल्यांकन सम्पन्न हो सके। (ii) स्वदेशी बनाम चीनी - भारत सर्वसमर्थ देश बने इसके लिए महासंघ द्वारा सभी शिक्षार्थियों व कार्यकर्त्ताओं को चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक दीर्घकालीन अभियान चलाने का आह्वान करते हुए केन्द्र व राज्य सरकारों से स्वदेशी के प्रोत्साहन, संवर्द्धन व संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने की माँग की है। (iii) शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलम्ब किया जाए - शिक्षा एवं शिक्षकों की लम्बे समय से अनिर्णीत सभी समस्याओं का केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा त्वरित रूप में समाधान करने की माँग की गई।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रभु देशपाण्डे ने महासंघ के संविधान अनुसार चुनाव सम्पन्न कराए तथा सर्वसम्मति से आगामी तीन वर्षों के लिए चुने गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की। नवीन कार्यकारिणी में श्री जगदीश प्रसाद सिंघल (राजस्थान)-अध्यक्ष, श्री शिवानंद सिंदनकेरा (कर्नाटक)-महामंत्री, डॉ. निर्मला यादव (उत्तर प्रदेश)-अतिरिक्त महामंत्री, श्री महेन्द्र कपूर (दिल्ली केन्द्र)-संगठन मंत्री, श्री ओमपालसिंह (लखनऊ केन्द्र)-सहसंगठन मंत्री, श्री महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)-उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी, श्रीमती प्रियंवदा सक्सेना (महाराष्ट्र)-महिला संवर्ग प्रभारी, प्रो. प्रग्नेश शाह (गुजरात)-उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा संवर्ग, डॉ. रेखा भट्ट (राजस्थान)-

सचिव महिला संवर्ग, डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)-सचिव उच्च शिक्षा संवर्ग, डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)-सहसचिव उच्च शिक्षा संवर्ग, श्री संजय राउत (मध्यप्रदेश) -कोषाध्यक्ष, श्री विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)-प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख, श्री बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान)-पश्चिम क्षेत्र प्रमुख शामिल है। समारोप सत्र में रा. स्व. संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख श्री अनिरुद्ध जी देशपाण्डे ने उद्‌बोधन देते हुए कहा कि संगठन के विकास की गति में कार्यकर्त्ताओं की प्रमुख भूमिका है और श्रेष्ठता स्थापित करने का कार्य शिक्षा के माध्यम से ही करना है। अध्यक्षीय उद्‌बोधन में डॉ. विमल प्रसाद जी अग्रवाल ने सभी कार्यकर्त्ताओं को परिवर्तन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

3. **सेवा कार्य** - संगठन की अलवर इकाई के कार्यकर्ताओं ने बीबीरानी प्रवास कर गाडिया लुहारों के परिवारों से सम्पर्क किया तथा उन्हें खाद्य सामग्री व वस्त्रों का वितरण किया। संगठन की दयानंद महाविद्यालय अजमेर इकाई ने भारत विकास परिषद् व एन.सी.सी. के सहयोग से सौ यूनिट रक्तदान किया।

सुखद शीतकालीन अवकाश की शुभकामनाओं एवं 8-9 जनवरी को बीकानेर अधिवेशन में आपसे साक्षात् मिलने की आकांक्षा के साथ

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

पहले सुनो, तब मनन करो और अन्त में सब द्विविधा को छोड़कर अपने अन्तःकरण को बाह्य प्रभावों की ओर से बन्द कर लो और अपने अन्दर सत्य के पोषण में लग जाओ। एक विचार को केवल उसके नयेपन से आकर्षित हो अपना लेना और फिर उससे भी नये विचार के लिए उसको त्याग देने की वृत्ति से ही पूरी शक्तियाँ बिखर जाने का भय है। एक विचार लो, उसी का चिन्तन करो, उसे अन्त तक पहुँचाओ और जब तक उसके छोर पर न पहुँचो, उसे त्यागो मत। जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गया है, उसे ही प्रकाश के दर्शन होते हैं। जो इधर-उधर ध्यान बांटते हैं, वे कोई लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाते। वे कुछ क्षणों के लिए बड़ा जोश दिखाते हैं, किन्तु वह शीघ्र ठण्डा हो जाता है।

- स्वामी विवेकानंद